loss and is unable to meet the demand of the public;

(b) whether Government are considering any proposal to give some subsidy to the Delhi Milk Scheme; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) The Delhi Milk Scheme worked at a loss upto 1965-66. In 1966-67, the accounts for which are under finalisation, a marginal profit is expected The Delhi Milk Scheme is handling only about 2.16 lakh litres of milk as against an estimated requirement of 5 00 lakh litres in the city It is unable to meet the entire requirement of the city due to shortage in procurement of milk

(b) Delhi Milk Scheme is a department of the Government of India The loss resulting on the working of the Scheme, is, therefore, borne by the Government of India There is no question of giving some subsidy to D.M S

(c) Does not arise

दिल्ली में दूध और खोये से तैयार होने वाली मिठाइयों पर प्रतिबन्ध

*476. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री आ० सुन्दर लाल :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री वी० बं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में दूध की कमी के कारण दूध और खोये से तैयार होने वाली मिठाइयों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप अनेक लोग बेरोजगार कर दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो दूध की कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) . (क) जी हां ।

(ख) प्रतिबन्ध अगस्त 1967 के अन्त तक रहेगा । बाद में दूध से बनी मिठाई-व्यापार से सबंधित लोग दूध से बनी मिठाई को छोड कर अन्य मिठाइया बेच सकते हैं । इस प्रकार इस आदेश से उत्पन्न बेकारी की स्थिति में सुधार हो जायेगा ।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना ने दूध की उपलब्धि को बढाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं —

(1) दूध सप्लाई करने वालो के साथ फर्म के अनुबन्ध हुए है जिनके अनुसार यदि विभिन्न मौसमो में दूध की स्वीकृत मात्रा की सप्लाई न हुई तो 5 रुपये प्रति विन्टल के हिसाब से जुर्माना होगा ।

(2) दूध सप्लाई करने वालो के कमीशन का दर जनवरी 1967 से बढा दिया गया है ।

(3) योजना का उपलब्धि क्षेत्र बढा दिया गया है । करनाल से लगभग 20 मील दूर हरियाणा मे दूध की विभागीय उपलब्धि के लिए एक नया उपलब्धि क्षेत्र ले लिया गया है ।

(4) परिवहन को सरल बनाने तथा दूध एकत्रित करने के लिए 10 ट्रक तथा 5 जीपें खरीद ली गई है।

(5) दिल्ली दुग्ध योजना के मिल्क शैड के लिए कुछ मधन पशु विकास कार्यक्रम स्वीकृत किये गए है। इन कार्यक्रमो के फलस्वरूप सबधित क्षेत्रो मे दूध उत्पादन मे वृद्धि होने की सम्भावना है।

(6) क्षेत्र मे गाय के दूध की उपलब्धि बढाने के लिए प्रतिदिन एक लाख लिटर दूध की क्षमता वाला एक बेलमिंग स्टेशन बीकानेर मे स्थापित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(7) दिल्ली प्रशासन द्वारा 17-5-67 से खोया, रबडी, पनीर तथा दुग्ध पदार्थो के आयात, निर्माण तथा बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जिससे योजना को दूध की सप्लाई कायम रखने मे सहायता मिली है।

Ban on Export of Milk to Delhi from Haryana and Uttar Pradesh

*477. **Shri B. S. Sharma:**
Shri A. B. Vajpayee:
Shri Balraj Madhok:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri Hukam Chand Kachwai:
Shri Ram Singh Ayarwal:
Shri Onkar Singh:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Uttar Pradesh and Haryana Governments propose to ban the export of milk to Delhi;

(b) if so, whether Government have taken up this question with the State Governments concerned in view of the acute shortage of milk in Delhi; and

(c) if so, the results thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

Rice from Burma and Spain

*478. **Shri Jyotirmoy Basu:**
Shri Virendrakumar Shah:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether any rice was due to come from Burma;

(b) if so, its quantity and the terms and conditions thereof;

(c) whether any rice is a so due to come from Spain; and

(d) if so, the terms and conditions thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) and (b). The quantity of rice to be imported from Burma during 1967 under the existing arrangements is 215 thousand metric tons, of which over 100 thousand metric tons has already arrived. The shipments are required to be completed by the end of 1967. The payment for the rice is to be made in Pounds Sterling

(c) and (d) Two contracts have recently been entered into with two private parties for the import of 30 000 metric tons of Spanish rice Shipments of this are to be completed by about the midd'e of August this year The payment for the rice is to be made in Pounds Sterling.

Agricultural Prices Commission

*479. **Shrimati Sharda Mukerjee:**
Shrimati Tarkeshwari Sinha:
Shri Inder J. Malhotra:
Shri M. Amersey:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the present composition of the Agricultural Prices Commission;